भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.1872

28 जुलाई, 2022 को उत्तर के लिए

हडको द्वारा ऋण

1872. डॉ. पोन गौतम सिगामणि:

श्री कुलदीप राय शर्माः

डॉ. सुभाष रामराव भामरे:

डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस.:

श्री धनुष एम. कुमार:

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:

श्री सी. एन. अन्नादुरई:

श्री जी. सेल्वम:

श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:

श्रीमती मंजुलता मंडल:

श्री गजानन कीर्तिकर:

डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:

क्या **आवासन और शहरी** कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड (हडको) द्वारा विभिन्न योजनाओं के लिए ऋण प्रदान करने के प्रावधान और मानदंड क्या हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान हडको द्वारा वित्तपोषित योजनाओं की संख्या कितनी है;

(ग) क्या हडको द्वारा वित्तपोषित कुछ योजनाओं को उक्त अवधि के दौरान कुछ राज्य सरकारों द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और हडको द्वारा वित्तपोषित योजनाओं को राज्यों के लिए अधिक व्यवहार्य बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या घरों के निर्माण के लिए बड़ी संख्या में राज्यों ने हडको से सहायता की मांग की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर हडको की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) चालू वित्त वर्ष के दौरान हडको के संसाधन आधार को बढ़ाने और इसके कारोबार का विस्तार करने के लिए सरकार द्वारा अन्य कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री कौशल किशोर)

(क): आवास और शहरी विकास निगम (हुडको) कंपनी के संगम ज्ञापन में मुख्य उद्देश्यों के अनुसार आवास और अवसंरचना क्षेत्र में परियोजनाओं को शुरू करने के लिए ऋण सहायता प्रदान करता है। प्रतिभूति और अदायगी तंत्र की उपलब्धता के आधार पर राज्य सरकार/एजेंसियों को ऋण प्रदान किया जाता है, जो परियोजना के प्रकार/प्रकृति के आधार पर भिन्न-भिन्न हो सकते हैं। हुडको परियोजना के वित्तपोषण से पहले परियोजनाओं की तकनीकी व्यवहार्यता, उधारकर्ता की कानूनी पात्रता और परियोजना की वित्तीय व्यवहार्यता को जानने के लिए परियोजनाओं का विस्तृत मूल्यांकन करता है।

(ख): पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान हुडको द्वारा स्वीकृत ऋण राशि सहित योजनाओं की संख्या निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	योजनाओं की संख्या	स्वीकृत कुल ऋण राशि (करोड़ रुपये में)
2019-20	31	13,512.38
2020-21	24	5,166.29
2021-22	40	18,024.58
2022-23 (30.06.2022 तक)	6	463.10

(ग): संबंधित राज्य सरकारों के सैद्धांतिक अनुमोदन के बाद ही अनिवार्य रूप से, वित्तीय सहायता के लिए योजनाएं प्राप्त होती हैं। हुडको राज्य सरकार/एजेंसियों को स्वीकृति पत्र के माध्यम से मंजूरी देता है, जिसमें ऋण के नियम और शर्तें शामिल होती हैं। हुडको के उक्त प्रस्ताव को राज्य सरकार/एजेंसियों द्वारा स्वीकार किया जाता है और तदनुसार ऋण के संवितरण से पहले मंजूरी शर्तों के अनुसार सभी आवश्यक सरकारी अनुमोदन प्राप्त किए जाते हैं।

(घ): इस समय, लगभग 20 योजनाएं ऐसी हैं, जिन्हें 13,158.76 करोड़ रु. की ऋण राशि वाली राज्य सरकार की गारंटी प्राप्त है, जहां उधार लेने वाली एजेंसियों द्वारा मंजूरी शर्तों का अनुपालन अभी किया जाना है।

योजनाओं की व्यवहार्यता के संबंध में, राज्य सरकारें आम तौर पर पर्याप्त राजस्व पूल उत्पन्न करने के लिए टैरिफ/अन्य शुल्कों में संशोधन करती हैं, जिसका उपयोग ओ एंड एम की लागत, हुडको के बकाए की अदायगी आदि के लिए किया जा सकता है। चूंकि हुडको वित्तपोषण बड़े पैमाने पर सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं जैसे कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आवास, मुख्य/ उपयोगी अवसंरचना संबंधी परियोजनाएं जैसे जलापूर्ति, सीवरेज, सड़कों, और सामाजिक अवसंरचनाएं जैसे अस्पतालों आदि अवसंरचना का प्रबंधन करता है,

जो गैर-लाभकारी और लंबी अवधि वाली होती हैं, राज्य के बजट संसाधनों या सरकार के अन्य राजस्वों के माध्यम से हुडको को धन वापस किया जाता है।

(ङ): जी, हां। राज्य सरकार की एजेंसियां प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी/ग्रामीण) के तहत आवास योजना के कार्यान्वयन के लिए हुडको से वित्तीय सहायता प्राप्त करने में गहरी दिलचस्पी दिखा रही हैं और ऐसे अन्य कार्यक्रम मुख्य रूप से शहरी/ग्रामीण गरीबों को लाभान्वित कर रहे हैं। विगत 3 वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान स्वीकृत आवास योजनाओं का ब्यौरा इस प्रकार है:

वर्ष	स्वीकृत आवास योजनाओं की संख्या	कुल स्वीकृत ऋण राशि (करोड़ रुपये में) - निवल
2019-20	7	3,224.07
2020-21	9	526.90
2021-22	12	1,746.78
2022-23 (30.06.22 तक)	-	-

(च): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय आवश्यकता पड़ने पर विभिन्न पहलुओं पर हुडको की सहायता करता है।

***